

*242. [The questioner (Prof. Sourendra Bhattachargee) was absent. For answer, vide col. 43-44 infra].

*243. [The questioner (Shri Vishwasrao Ramrao Patil) was absent. For answer, vide cols. 44-45...infra].

Publication of Technical and Scientific Journals in Hindi

*244. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:†

SHRI PRAMOD MAHAJAN:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of research papers are being published in Japanese and Chinese in advanced areas of Science and Technology, Space, Electronics Bio-technology etc.;

(b) whether there is any proposal for publishing research journals on Electronics and other areas in Hindi; and

(c) what is the scheme to promote research publications in Hindi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA):
(a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

The use of the Japanese and the Chinese languages for publications in advanced areas of Science and Technology has been in vogue in Japan and China for a long time.

(b) and (c) The Government of India is encouraging publications of a high standard in Hindi on scientific and technical subjects including research papers. The Department of Science and Technology has initiated a scheme of awards with cash prizes

of Rs. 15,000/-, Rs. 10,000/- and Rs. 5,000/- annually as 1st, 2nd and 3rd prizes respectively, for publication of original books of high standard in Hindi in the following areas: Physics, Chemistry, Life Sciences and Engineering Sciences.

The examples of science periodicals in Hindi are: 'MAUSAM' (published by the India Meteorological Department—abstracts of articles in Hindi); 'PARMANU' (published by the Department of Atomic Energy); 'URJA BHARAT' (published by the Department of Non-Conventional Energy Sources); 'ANTARIKSH BHARAT' (published by the Department of Space); 'SROTE' (published by the Department of Science and Technology); and 'PARYAVARAN' (published by the Ministry of Environment and Forests). The Department of Space also publishes Hindi books on various technical developments and projects such as SLV-3 launcher, and remote sensing.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, जिन आनन्द की अनुभूति संसद के किसी सदस्य को अपना प्रश्न बकाया देते हुए होती है वैसी ही अनुभूति मुझे अपना प्रश्न काराधिक प्रश्न पूछते हुए हो रही है। सभापति जी, मेरी सदस्यता के एक साल पांच महीने और दो दिन के बाद मेरे किसी प्रश्न ने इतनी गुलबो पत्तों के अंदर अपना स्थान प्राप्त किया है। सभापति जी, मैं आनन्द तिरिक से भरते हुए आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूँ कि अभी कल ही भारतीय भाषाओं और कंप्यूटर विषय पर एक विशेष बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री जी की ओर से किया गया था। मैं महोदय से आभार प्रकट करती हूँ उनके प्रति, क्योंकि संसद सदस्यों की बैठकें आयोजित किया जाना, उनसे सलाह मांगा जाना, यह तो संसदीय प्रणाली में आम बात है। लेकिन संसद में पूछे गये प्रश्नों के आधार पर, सासदों की रचि का आकलन करके उस विषय विशेष पर बैठक आयोजित करना

†The question was actually asked on the floor of the House by Smt. Sushma Swaraj.

और संवाद के सब के चलते, स्वयं प्रधानमंत्री का उसकी अध्यक्षता करना यह अपने आप में एक आदर्श उदाहरण है। मैं हृदय से प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि यह इसकी गंभीरता और इस विषय में उनकी रुचि का परिचायक है। इसलिये मैं पुरी आशा और विश्वास के साथ यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मंत्री महोदया ने जवाब दिया है, उस में हिन्दी में शोध-पत्रिकाओं के प्रकाशन का क्या प्रस्ताव था, यह मेरा सवाल था। उसका सीधा जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता था। लेकिन जवाब सीधा नहीं आया। मेरे सवाल का भाग (ख) यह था कि क्या इलेक्ट्रानिकी तथा अन्य क्षेत्रों में हिन्दी में शोध पत्रिकाएँ प्रकाशित किए जाने का कोई प्रस्ताव है। इसका सीधा जवाब आ सकता था हाँ या नहीं। लेकिन जवाब धृष्टवदर ढंग से पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन का दिशा दिया गया। सभापति जी आप जरा जवाब को देखें तो इसमें कहा गया है कि मौलिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए पुरस्कार का प्रावधान है पहला, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की राशि दी जाती है। विज्ञान पत्रिकाओं के कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं। मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि पुस्तकों और पत्रिकाओं में फर्क है। पत्रिका और शोध पत्रिका में भी फर्क है। पुस्तक एक स्थायी चीज होती है जबकि पत्रिका में निरंतरता और गतिशीलता होती है। उसी तरह पत्रिका आर्किवरी जर्नल होती है जबकि शोध पत्रिका एक रिसर्च जर्नल होती है। मेरा प्रश्न यह है कि कल आपने स्वयं यह बात मानी थी कि हिन्दुस्तान में केवल दो फीसदी लोग अंग्रेजी जानते हैं इसलिए यदि हम कंप्यूटर को जनजीवन से जोड़ना चाहते हैं तो हमें भारतीय भाषाओं को कंप्यूटर नेटवर्क पर लाना होगा। मेरा आपसे यह कहना है कि हिन्दी में शोध पत्रिका का प्रकाशन इस दिशा में मील का एक पत्थर साबित होगा। इसलिए क्या आप हिन्दी में शोध पत्रिका के प्रकाशन के प्रस्ताव पर विचार करेंगे? पुस्तकों के प्रकाशन से या पत्रिकाओं के प्रकाशन से यह मसला हल नहीं होगा और समस्या ज्यों की त्यों

बनी रहेगी। शोध पत्रिका के प्रकाशन का कोई निश्चित प्रस्ताव आपके पास है या नहीं, यदि नहीं है तो क्या लाएंगे? यह मेरा सवाल है।

THE PRIME MINISTER (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): Sir, I entirely agree that the answer which has been given is a little more general and it does not specifically state what the position in regard to research journals is. The position as it happens to be is that we do not have research journals, as we understand, in Hindi. We have gone into it and we would like to have research journals also started in Hindi and probably in other languages, wherever it is possible. When they could do it in Chinese, Japanese, German and so on, there is absolutely no reason why we should not be able to do it in our languages today. There is a question of terminology, but we could always use English words until the terminology, the equivalent terminology, comes into complete usage and this can be done. All I have to say is that those countries where we have research journals, they do also have research of a very high order on a very wide scale. What is possible in India now is that whatever research we are doing, it will be contained in the research journals, but at the same time our research base being not very wide, we will have to be take material from other journals in other languages from other countries and also the information in regard to research on a particular subject being carried out in other countries. And it, cannot be an omnibus journal, it has to be a specialised journal. If it is medical, it has to be medical; if it is educational, it has to be educational, etc. because research in such a big basket that we cannot have all the subjects contained in one basket. Therefore, this is a very wide programme. I would certainly like to make some beginning at the earliest and I would like

to assure the Members that this lacuna has been realised, we have found it and we would like to remove it as quickly as possible.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति महोदय, बहुत ही अश्वस्त करने वाली उत्तर देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। एक ही बात, जहाँ से उन्होंने अपना जवाब समाप्त किया, वहीं से मैं दूसरा प्रश्न प्रारम्भ करती हूँ। इनाहबाद विश्वविद्यालय की विज्ञान और अनुसंधान परिषद गणित और भौतिकी में अपना प्रकाशन कर रही है, केवल थोड़ा सा और अनुदान दिये जाने पर वह इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर पर भी शोध पत्रिका प्रकाशित कर सकती है। तो केवल थोड़ा सा और अनुदान देकर इस तरह का शोध प्रकाशित करवाने पर आप क्या विचार करेंगे ?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO:
Sir, we will tell the University Grants Commission to pay special attention to this aspect.

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, सदस्या बहिन सुषमा जी ने प्रधान मंत्री जी को दी बातों पर जो बधाई दी उसमें मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ, कल की बैठक के लिए भी और शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन का विचार करने लिए भी। प्रधान मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि शोध पत्रिकाएँ तो तब निकलेंगी जमें शोध होगा, बिना शोध के खाली शोध पत्रिकाएँ नहीं निकल सकती हैं, इसलिए शोध होना चाहिए और कुछ शोध के लिए मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्राचीन हिंदुस्तान ने दुनियाँ को ज्ञान-विज्ञान दिया है और अब हम सब जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे धारा हम दुनियाँ के सारे गणयंत्रों, कंप्यूटर्स को एक भाषा दे सकते हैं। समस्या यह है कि जो संस्कृत जानता है वह गणयंत्र, कंप्यूटर को नहीं जानता है और जो कंप्यूटर जानता है वह संस्कृत को कम जानता है और इसके कारण हमें आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। क्या इस दृष्टि से विभिन्न जो पत्रिकाएँ होंगी

उत्तम केवल हिंदुस्तान की शोध पत्रिकाओं पर ही नहीं बल्कि संस्कृत और गणयंत्रों को इकट्ठा करने वाली शोध पत्रिकाओं पर भी क्या सरकार विचार करेगी, यह मेरे प्रश्न का एक हिस्सा है।

दूसरा हिस्सा मेरे प्रश्न का यह होगा कि ये जो नगद पुरस्कार हैं वह बहुत कम हैं क्योंकि 15 हजार रुपये किसी पुस्तक पर पुरस्कार हो तो मझे लगता है कि यह उत्तम कवर पेज की भी कीमत नहीं होगी। तो क्या इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे ?

तीसरा, सभापति जी से मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि यह जो "ख" और "ग" आदि इकट्ठा करने की पद्धति है यह अच्छा नहीं है। अगर "क", "ख", "ग" और "ग" भूछा है तो उत्तर भी "क", "ख" और "ग" होना चाहिए। मंत्रालय चाहे सबको इकट्ठा करे लेकिन यह अच्छा नहीं है।

मैं आशा करता हूँ कि प्रधान मंत्री जी ने बहिन सुषमा जी को जैसे संतोष दिया है वैसे मुझे भी देंगे।

श्री पी. वी. नरसिंह राव : श्रीमन्, बात ऐसी है कि पहले तो हमारा शोध शुरू हो जाए, बड़े पैमाने पर हो जाए। तो उसमें से हम शोध पत्रिकाएँ निकाल सकेंगे, ला सकेंगे और उसमें जितनी कुछ इन्फार्मेशन चाहिए वह सब हम दे सकेंगे। दूसरी बात यह है कि यह जो पुरस्कार होता है, इस पुरस्कार की राशि के बारे में मैं इससे पहले ही कह चुका हूँ कि यह राशि कोई ऐसी नहीं है जिसको हम बड़े वर्ग के साथ कहीं कह सकें कि यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इसमें कुछ बढ़ोतरी करने की अवश्य कोशिश की जाएगी।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI:
Sir, our hon. Member has enquired about the proposal for publishing research journals on electronics and

others in the Hindi language. The hon. Member is very much concerned about the advanced areas of electronics, etc. I would like to inform the Prime Minister that there is a strong feeling in the South that the Central Government is developing only one language. It is true. If we go through the annual reports of all Ministries we will find a chapter describing about the actions taken or proposed to be taken to develop the Hindi language. But at the same time we do not find a single sentence about the development of other Indian languages. Therefore, I would like to know from the hon. Prime Minister whether there is any proposal with the Government of India to develop other Indian languages in the same way as it has done for the development of the Hindi language. It is a very important question. The unity and integrity of the nation lies in this question.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, there is an institution called "Telugu Academy" in Andhra Pradesh. I am not saying that it is unique. There may be similar institutions in other States in other language groups. But, if the work of the Telugu Academy for the last twenty years is examined you will find that the Academy has done everything that needs to be done, both on the technical side and the humanity side, in the Telugu language. We did have to face any number of obstacles in the beginning. There was apathy; there was lethargy; all these things were there, but we were able to push through the programme in a very successful manner and, I am sure, in Marathi and other languages also this is being done and, I am equally sure, that in Tamil the work is no less. So the development of Indian languages initiated by the Central Government by paying Rs. 1 crore to start with for each language group has gone on so well in certain languages, not so well in other languages, I must admit. But this programme has been very successful and to say that the other languages have not developed

at all, I would say, is not only an exaggeration, it is also far from truth.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am not satisfied with the answer. I have specifically asked about the working of the Central Government here in Delhi. We cannot find a single sentence about developing regional languages.

MR. CHAIRMAN: They have given Rs. 1 crore to each language. The State Government in Andhra Pradesh took the initiative when he was the Chief Minister and it is doing so well. The other Chief Ministers can also do the same.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: We are asking for equal treatment of the other Indian languages on a par with Hindi. What they have done for Hindi, they have not done for other languages. The State Governments are saying that Rs. 1 crore is not sufficient.....

MR. CHAIRMAN: Dr. Ratnakar Pandey.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I am not satisfied with the answer.
(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. I have called Dr. Ratnakar Pandey.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : महासहिब सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने बल जो कंप्यूटर के सफू में मोटिंग का थी, उसमें मुझे बुलाया था, लेकिन अपनी मूर्खता और लापरवाही के कारण मैं उसमें पहुँच नहीं पाया। उसके लिए मैं ... (व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : पहली बार प्रहसित हुआ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्योंकि इतना बड़ा अवसर प्रधान मंत्री जी ने दिया कि पारे सांसद जो इसमें रुचि रखते हों, वह आयें और उनके साथ बैठ कर, वैसे भारतीय भाषाओं का कंप्यूटर में प्रयोग हो, इसमें आपने रुचि ली, इसके लिये हम आपको भारतीय भाषाओं और हिंदी

'त की ओर से बढ़ाई देते हैं और अब मैं प्रार्थना यह कर रहा हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेस और जो आपका परमाणु ऊर्जा विभाग है, इन तीनों की जो हिंदी संसदीय राजभाषा एडवाइजरी समिति है मैं उसका फॉइंडर मेंबर हूँ और मुझे यह कहने में खुशी है कि सन् 1984 में इन संस्थाओं ने काम करना शुरू किया। परमाणु ऊर्जा और स्पेस सेंटर इलेक्ट्रॉनिक से बढ़ कर के तकनीकी शब्द, जिसकी टेक्नोकैलिटी की बात होती है, भारतीय भाषाओं के प्रयोग के लिए कहीं नहीं है और जितना सुंदर प्रा. वेद लोगों ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में टेक्नोकैलि लिटरेचर निकाला है, उसको क्या आदर्श मान कर के जिनहल्ल श्वग भारत सरकार के मंत्रालय के टेक्नोकैलिटी को बढ़ाना बना करके उसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग हम नहीं कर सकते, एक बढ़ाना बनति है और उच्च मंत्रालय की ओर से इस, बीस या पच्चीस हजार छपड़े का पुस्तकार प्रति वर्ष आप कवचपणि करते और कितना छाते हैं (व्यवधान)

श्री समापति : आप प्रश्न कर लें।

डॉ० रत्नाकर पाण्डेय : मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि अंग्रेजी के स्थान पर कंप्यूटरों में हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रचलन में जब आपने रुचि ली है, तो क्या कोई टाईम-बाउंड प्रेमबर्क उस पर लगा रहे हैं और कब तक उसको लगा देंगे? और जो टेक्नोकैलिटी को बढ़ाना बना कर राजभाषा की उपेक्षा करने की भारत सरकार ने आदत बना ली है, उसको खत्म करके एक आदर्श मान करके इन तीन मंत्रालयों का उसी आधार पर काम शुरू करायेंगे, यह मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ?

SHRIMATI MARGARET ALVA:
We have a programme for introduction...

डॉ० रत्नाकर पाण्डेय : माननीय समापति जी, मुझे आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करनी है कि

मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की है कि मेरे प्रश्न का जवाब वह न दें। मैंने कल की मीटिंग में अपनी लापरवाही और अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांग ली है और उसके बाद भी मेरे प्रश्न का जवाब प्रधान मंत्री जी न दें, यह थोड़ा सरी गरिमा के ... (व्यवधान)

श्री समापति : अब यह तो मुश्किल हो जाएगा। यदि हरेक कहे कि मेरा जवाब प्रधान मंत्री दें, तो मुश्किल हो जाएगा।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : इन विशेष परिस्थितियों में मैं ही जवाब दे रहा हूँ।

श्रीमन्, यह भाषा ऐसी चीज है जिसको हुकम देकर हम चला नहीं सकते हैं। समयबद्ध बहुत ठीक है..... लेकिन कई ऐसे विषय हैं, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो होते-होते होते हैं। एकदम हमारे कहने से कि अमुक समय तक यह होना ही चाहिए, यह संभव नहीं होता और भाषा का भी यही है। हमारा यह अनुभव रहा है भाषा के क्षेत्र में काम करते-करते कि हमें किसी भी चीज की तेजी को और बढ़ाने की छतिम कोशिश नहीं करनी चाहिए। उससे असर उलटा पड़ता है। अभी कंप्यूटरों की बात ले लें। हमारे यहाँ लोगों की समझ में एक यह बात आ गई थी कि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो या तो बहुत बड़े धनवान लोगों की चीज है या फिर ऐसे लोग, जो हमारे अजाम से, जनसाधारण से जिनका कोई संबंध नहीं है, उनके इस्तेमाल की चीज है। अभी तक लोगों की समझ में यह नहीं आया है कि कंप्यूटर एक टूल है, आपके विद्यार्थी के हाथ में जैसे लॉगिथम टेबल होता है, आज कंप्यूटर या कैलकुलेटर हो तो उसको कितनी सुविधा हो सकती है, यह लोगों की समझ में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि एक तरह से उसके जिम्मेवार हम भी हैं। जहाँ कंप्यूटर की बात आई राजनीतिक भाषा में हम यह कहने लग गए कि यह तो ऐसे लोगों का काम है, यह ऐसे लोगों की बात है, यह हाई-

लोग हैं, यह बहुत बड़े ऐसे लोग हैं जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, तो एक तरह से इसके जिम्मेवार हम भी हैं। इसलिए इसका प्रायश्चित्त हमें भी करना पड़ेगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे करना पड़ेगा, पाण्डेय जी को करना पड़ेगा, सारे पक्षों के नेताओं को करना पड़ेगा, तभी यह बात, कंप्यूटर लोगों तक पहुँच सकता है। उसकी पहुँच ही जहाँ नहीं है, उसकी एक्सप्लिबिलिटी ही नहीं है, लोग समझते हैं कि इसे हमें छुना नहीं चाहिए और उसमें ऐसी एक मिस्ट्री हो गई है, डिमिस्टीफिकेशन को पहले जरूरत है कि यह क्या है, यह कैसी चीज है, इसमें कोई ऐसा राज होगा जिसे हम नहीं जानते होंगे, यह कोई बड़ा परम रहस्य होगा। जब तक यह बात नहीं निकल जाती कंप्यूटर को हम मामूली संयंत्र के रूप में लोगों के सामने नहीं पेश करेंगे और उनकी फेमिलियरिटी उस से नहीं हो जाएगी, परिचय उसमें नहीं होगा, तब तक यह काम आगे नहीं बढ़ेगा और भाषाओं के बारे में बहुत कुछ काम भी तो करना है। अंग्रेजी में जो सुविधा है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग की सुविधा है, डी-बेस की सुविधा है, सभी सुविधाएँ हैं, आज वर्ड प्रोसेसिंग को ले लीजिए, आपके सारे कमांड्स अंग्रेजी में आते हैं, हिन्दी में वर्ड प्रोसेसिंग होता है, तेलुगु में वही वर्ड प्रोसेसिंग होता है, लेकिन उस पर कोई किताब नहीं लिखी गई। आपको तो सैकड़ों पुस्तकों के लिखने और लिखवाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि संकल्प हमारा बिल्कुल ठीक है, यह हमको करके रहना है, लेकिन इसमें समय लगेगा और जब संकल्प ठीक है और सही दिशा में हूँ जा रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा जल्दी करके उसको उलटाना नहीं चाहिए। उसको धीरे-धीरे गति देने की कोशिश करनी चाहिए। यही सरकार करना चाहती है।

श्री मोहम्मद सलोम : सरावनीय सभापति सहोदय, प्रधान मंत्री जी ने, जो जवाब यहाँ दिया गया, उसके बारे में हमें रोशनी डाली और मुझे अच्छा लगा, लेकिन जो प्रश्न था उसमें रिसर्च जर्नल

के बारे में, शोध पत्रिका के बारे में ही था, उसमें बढ़ करके ऊँचे दर्जे में हिन्दी में किताबें लिखने के बारे में यह जवाब भी आ गया, जो प्रश्न में नहीं था वह भी आ गया। हम शोध पत्रिका के बारे में बात नहीं कर सकते, अगर हाई स्टैंडर्ड उस जमान में, भाषा में किताब नहीं रहेगी। तो मैं यह आग्रह करूँगा कि यहाँ जो लिखी है कि फिजिक्स कैमिस्ट्री, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग साइंस में यह दिया गया है कि उसमें ऊँचे दर्जे की किताबें लिखी जाएँ और उसके लिए रिवार्ड भी दिया जाएगा, उसमें कंप्यूटर साइंस भी जोड़ लेना चाहिए। आप जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी कंप्यूटर साइंस में रुचि रखते हैं, कंप्यूटर जो साफ्टवेयर है, उसे भारतीय भाषा में डिवेलप करने के लिए, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में प्रधान मंत्री जी ने कहा तो उत्साह देने के लिए ऐसी स्कीम लागू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट के कंप्यूटर साफ्टवेयर की भारतीय भाषा में बनना हम जनता के पास कंप्यूटर को नहीं ले जा पायेंगे। मेरी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वह जो उत्तर यहाँ पर आया है हिन्दी भाषा में इस किताब को बढ़ावा देने के लिए; लिखने के लिए जो स्कीम लागू किया गया है भारतीय अन्य भाषाओं में भी विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान जो है इसकी चर्चा के लिए, उत्साह देने के लिए कोई स्कीम लागू करेंगे, खास करके जो स्टेट में यह काम कर रहे हैं, वह लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसे कोई अनुदान देने का बंदोबस्त करेंगे ताकि ऊँचे दर्जे की किताबें लिखी जाएँ। कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर यूनिवर्सिटी, विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अपनी जगहों में वहाँ विज्ञान की चर्चा की एक धारा रही है, जिससे आचार्य जगदीश चन्द्र बसु, प्रफुल्ल चन्द्र राय—ये जुड़े हुए हैं। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अनुदान दिया जाएगा हिन्दी के लिए; उसके साथ-साथ मैं कहूँगा कि रोजनल यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ अनुदान का बंदोबस्त किया जाए ताकि वह अपनी भाषा में भी विज्ञान की चर्चा कर सकें।

श्री पी. बी. नरसिंह राव : मैंने जब इनाहाबा की बात कही तो कोई खास इनाहाबा से पक्षपात करने के लिए नहीं कही। बात यह है कि जहाँ कहीं विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान मिलता है, उसमें इस बात के लिए खास ध्यान देना चाहिए, हम यह युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन को सुझाएंगे और जहाँ कहीं ऐसा सुझाव आएगा, ऐसा कोई कार्यक्रम होगा तो उसको अनुदान देने में कोई सदेह नहीं होता चाहिए और बराबर अनुदान दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अनुदान दिया जा रहा है, मेरा ऐसा विश्वास है, लेकिन फिर भी हम इसको डाल चैक करते हैं और उसको बताते हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, कंप्यूटर जहाँ तक मुझे ज्ञान है, एक डिस्टिंग्विश्ड स्लैव यानी अनुशासित गुलाम है और मालिक के हुक्म के अनुसार जो भी फीड किया जाता है वही देता है और इसकी शुष्प्राप्त सबसे पहले...

श्री सभापति : अब सवाल कर लो, इतिहास बताओगे तो समय निकल जाएगा, 45 मिनट हो चुके हैं।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह ग्रहलुवालिया : मैं प्रश्न पर हो आ रहा हूँ, कंप्यूटर से हम विदेश से तकनीक ला रहे हैं, पर कंप्यूटर की तकनीक की सृष्टि भारत में हुई थी। दस-पंद्रह वर्ष पहले "लीलावती" नाम की एक पुस्तक छपी थी, आप जानते होंगे, जिसमें कंप्यूटर का सारा डिजाइन दिया गया था। आज वह किताब भारत में उपलब्ध नहीं है। हॉलैंड में, जापान में, अमेरिका में उसका उनकी भाषा में संस्कृत से अनुवाद कर के वहाँ पुस्तक वहाँ मिलती है, पर भारत में उपलब्ध नहीं है। क्या प्रधान मंत्री महोदय "लीलावती" को संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर के या वहाँ की रीजनल लेवेलज में अनुवाद कर के वहाँ टेक्नीशियनों को उपलब्ध कराएंगे?

श्री पी. बी. नरसिंह राव : जहाँ तक मुझे स्मरण है "लीलावती" यहाँ भी उपलब्ध थी क्योंकि हमने उसके बारे में सुना था। जब हम विद्यार्थी थे, "लीलावती" के बारे में हमने सुना था और कुछ पंक्ति ऐसे थे जिन्होंने "लीलावती" का अध्ययन किया था। अब मुझे नहीं पता कि इन दिनों में जब हम बहुत ज्यादा मुहजिब हो गए तो पुरानी किताबें लुप्त हो गयी हैं और दूसरी जगह जाकर उनको ढूँढना पड़ता है। अगर ढूँढना हो तो वह भी हम करेंगे। यह हम जानते हैं कि हमारे कई संस्कृत के महान ग्रंथ यहाँ से लुप्त हो गए हैं और उनका अनुवाद तिब्बत में मिलता है। वहाँ से फिर हम को वापस लाने की नीबत आई है। तो यह हुआ है। हमारी मीडिबल शताब्दियों में यह सारी चीज हुई है, लेकिन "लीलावती" के बारे में मुझे अच्छी तरह याद है कि वह यहाँ उपलब्ध थी कोई 50 साल पहले जब हम पढ़ते थे और अब भी है तो ठीक है, फिर उसको बाहर निकालन पड़ेगा। अगर नहीं है तो बाहर से लाने की कोशिश करनी होगी। यह हम जरूर करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Upendra.

SHRI P. UPENDRA: Sir, the Prime Minister is a great scholar, not only in one language but also in several languages... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: I am very happy that one Telugu man is praising another Telugu man!... (Interruptions)...

SHRI P. UPENDRA: Not that, Sir. He mentioned about the Telugu Academy and that is why I said it. But, Sir, he should be equally interested in the development of all the languages.

MR. CHAIRMAN: He was associated with the Telugu Academy.

SHRI P. UPENDRA: But that is not enough. The State-level Academies are not enough. There should be some other Central agency. The

Sahitya Akademi is there, but its scope is very limited. Not only is there a need for the development of these languages, but there is also the need for translation of great works from one language to another. What I would suggest is that just as there are Hindi directories in various Ministries, there should be a separate department for the development of Indian languages in the HRD Ministry. Therefore, will he consider setting up a separate department for the development of the Indian languages in the Human Resource Development Ministry? There are five Departments and I think he can add one more department to the Ministry for the development of the other Indian languages. Will he kindly consider this?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, I cannot answer this off-hand because there are some implications in this. The responsibility, the main responsibility, of developing the regional languages, other languages, would naturally lie on the State Governments and expertise is available there.

SHRI P. UPENDRA: What about co-ordination from the Centre?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Yes, we can consider that. But I have to look into it and see whether it is not being done. I will have to look into it. But, mainly it is the areas—I am not even talking about the Governments—I am talking of the areas where the language is a live language, it is spoken, it is growing, it is getting into the lives of the people, reflecting the lives and sentiments of the people, it is in those areas that it could be really developed. What we can do from here in order to encourage that process, that we can always see. If there is any inadequacy in it, we can certainly make it adequate.

MR. CHAIRMAN: Question No. 245.

रसायनों का निर्यात

* 245. श्री रणजीत सिंह :

श्री राम जेटमलानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 अगस्त, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "बिग पोटेन्शियल फॉर बसिंग केमिकल एक्सपोर्ट स्टडी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने "एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया" द्वारा गठित अध्ययन-दल की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रसायनों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि कोई योजना नहीं बनायी गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a) to (f) Yes, Sir. The new trade policy announced by the Government recently, which has brought about major reforms in the Exim Strip System and Advance Licensing, has been formulated after taking into account the various suggestions received from the trade and industry and the recommendations of such study reports.

SHRI RANJIT SINGH: Mr. Chairman, Sir, although the Minister has replied, still some portion needed clarification.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ranjit Singh.